क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480 सह संपादक : संदीप मौर्या
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 310, सोमवार, 10 दिसम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

महागठबंधन की बैठक में शामिल होंगे मुलायम सिंह यादव

लखनऊ एजेंसी। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का कहना है कि वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री व तेलगू देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह विपक्षी दलों की एकता के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक है और वह इसमें शामिल होंगे। शिवपाल यादव द्वारा बुलाई गई जनाक्रोश रैली में मुलायम ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि लगता है कि मुझे एक बार फिर साम्प्रदायिक ताकतों को हराने के लिए संघर्ष करना है। बताते चलें कि पिछले काफी समय से चंद्रबाबू नायडू सत्ताधारी एनडीए के खिलाफ लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। इसी मुहिम के तहत दिल्ली में सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव निपट जाने के बाद हो रही यह बैठक खासी महत्वपूर्ण होगी।

मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस परेशान है: शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली एजेंसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस परेशान हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग पर शक किया. अब वे मतगणना के समय बाधा पैदा करेंगे। हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को सतर्क और शांत रहने के लिए कहा है। शनिवार को शिवराज ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का विश्वास जताते हुए कहा कि उनसे बड़ा ''सर्वेयर कौन है। वह दिन-रात जनता के बीच रहते हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में परिवार के साथ अवकाश बिताने के बाद शनिवार की सुबह वहां से रवाना होने से पहले चौहान ने एग्जिट पोल के सर्वे के सवाल पर मीडिया से कहा, ''मुझसे बड़ा सर्वेयर कौन है। दिन-रात जनता के बीच रहता हूं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री चौहान अपने परिवार के साथ आज दतिया पहुंचे। उन्होंने यहां पर प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठ पीतांबरा पीठ के दर्शन किये। मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी

अमेरिकन सिंगर बियोंसे पहुंची उदयपुर, परफॉर्मेंस के लेंगी 15 करोड़!

नई दिल्ली। ईशा अंबानी की प्री-वेडिंग सेरेमनी में देश-विदेश से मेहमानों का आना जारी है। रविवार को मशहूर अमेरिकन सिंगर बियोंसे भी उदयपुर पहुंचीं। वे यहां 60 डांसर के साथ परफॉर्म करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक संगीत सेरेमनी के लिए बियॉन्से लगभग 15 करोड़ रुपये ले रही हैं। प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए शनिवार को 90 से अधिक चार्टर प्लेन उदयपुर पहुंचे। जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन, उद्योगपति लक्ष्मीनिवास मित्तल, कुमार मंगलम बिड़ला, अनिल अग्रवाल, सुनील भारती मित्तल, उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सचिन तेंडुलकर, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, कटरीना कैफ़ करण जौहर, बच्चन परिवार, प्रियंका और निक जोनस सहित देश-दुनिया के शीर्ष कारोबारी शामिल हैं।

उदयपुर में शनिवार को ईशा अंबानी के विवाह पूर्व समारोह में शामिल होने पहुंचीं अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के साथ रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी।

यूपी: शिवपाल सिंह यादव की जनाक्रोश रैली में पहुंचे मुलायम सिंह यादव, जोश से भर गए कार्यकर्ता

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के मंच पर मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, अपर्णा यादव, राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव, मौजूद हैं।

लखनऊ। अलग पार्टी बनाने के बाद पहली बार सियासी ताकत दिखाने के लिए राजधानी लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में जनाक्रोश रैली (Jan Aakrosh Rally) कर रहे शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Yadav) के मंच पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व उनके बड़े भाई मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे। मुलायम के पहुंचते ही शिवपाल समर्थक जोश से भर गए। इस दौरान मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने शिवपाल यादव को शेर बताते हुए कहा कि आज का जनसैलाब इस बात का प्रुफ है कि शेर को चोट नहीं देनी चाहिये। उन्होंने लोगों से कहा कि आज बदलाव का समय है। कब तक गिनी चुनी पार्टी को मौका देंगे। 2019 में नए रूप में आगे आइये। इसी क्रम शिवपाल के बेटे व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने कहा कि, आज तक बहुत लोगों ने समाजवाद के लिए काम किया। हम हिन्दू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे। हम रोजगार के लिए बात करेंगे। हम अपनी सुरक्षा के लिए बात करेंगे। हम प्रगतिशील को ही अपना धर्म बनाएंगे। उसको आगे बढ़ाएंगे। योगी सरकार पर हमला करते हुए आदित्य ने कहा कि, आज लोग शहरों के नाम बदल रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर विकास करना है तो नए शहर बनाइए। इसको विकास कहते हैं। हमें समाजवाद को फिर से जिंदा करना होगा।

जनाक्रोश रैली: शिवपाल यादव ने कहा- दंगा भड़काना चाहती है भाजपा

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के मंच पर मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, अपर्णा यादव, राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव, एमएलसी मधुकर जेटली, पूर्व मंत्री शादाब फातिमा, शारदा प्रताप व पूर्व विधायक राजेंद्र यादव मौजूद हैं।

21 साल पहले राजकुमारी ने समाज से लड़कर की थी लव मैरेज, आज मांग रही हैं तलाक

नई दिल्ली। जयपुर के पूर्व राजघराने की बेटी और बीजेपी की पूर्व विधायक राजकुमारी दीया कुमारी के पति नरेंद्र सिंह से अलग होने का फैसला कर लिया है। पिछले काफी दिनों से दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। दीया कुमारी और उनके पति पिछले 5 सालों से अलग रह रहे थे। जयपुर राजघराने की राजकुमारी दीया कुमारी ने अपने लव मैरेज के 21 साल बाद पति नरेंद्र सिंह से तलाक मांगा है। दीया कुमारी ने फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाई है। उन्होंने जयपुर के गांधीनगर के महानगर फैमिली कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर पति से तलाक की इच्छा जताई है। दीया कुमारी जयपुर के पूर्व राज महाराजा सवाई भवानी सिंह और राजमाता पद्मिनी देवी की बेटी हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा जयपुर, दिल्ली व लंदन से की थी। दीया और सिवाड़ के कोठड़ा ठिकाने के नरेंद्र सिंह राजावत की शादी अगस्त 1997 में हुई थी और दोनों के दो बेटे और एक बेटी है।

यूपी : एटीएस ने संभाली प्रयागराज कुंभ मेले की सुरक्षा

लखनऊ। प्रयागराज कुंभ मेले में आतंकी हमले की साजिश विफल करने के लिए यूपी एटीएस ने अभी से मेले की सुरक्षा कमान अपने हाथ में ले ली है। एटीएस के ब्लैक कैट कमांडो दस्ते ने कुम्भ मेला परिसर में मॉक ड्रिल के साथ ही सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया है। मेला क्षेत्र अब 5 मार्च तक एटीएस के हवाले रहेगा।

यूपी एटीएस के आईजी असीम अरुण ने बताया कि कुंभ 2019 में किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। एटीएस की फील्ड इकाइयां सक्रिय हो चुकी हैं व षड्यंत्र की स्टेज से ही रोकथाम कर रही हैं। एटीएस ने पूर्व में आतंकियों के जो मॉड्यूल पकड़े थे उनसे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ था कि आतंकी बड़े धार्मिक आयोजनों पर हमले की योजना बना रहे हैं। पिछले दिनों एटीएस ने हिज्ब-उल-मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी कमरऊज्ज़मां को कानपुर से गिरफ्तार था। इसके अलावा तीन बांग्लादेशी आतंकी भी गिरफ्तार किए गए थे। आतंकियों के और मॉड्यूल पर भी काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि एनएसजी की एक टीम पूरे समय प्रयागराज में उपलब्ध रहेगी। इनके लिए एयर फोर्स या बीएसएफ के हेलीकॉप्टर का प्रबंध करने का प्रयास शासन द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही यूपी एटीएस की दो स्पॉट टीमें (स्पेशल पुलिस आपरेशंस टीम) मेला क्षेत्र में कैंप करेंगी। हर स्पॉट टीम में फाइटरों के साथ बम विशेषज्ञ, श्वान दल और स्नाइपर हैं। कुछ स्पॉट फाइटर मोटर साइकिलों पर होंगे ताकि वे तेजी से कहीं भी पहुंच सकें।

इंटेलिजेंस का साझा ग्रुप बनेगा

आईजी एटीएस ने बताया कि कुंभ पुलिस के 40 थानों पर एक एक क्यूआरटी नियुक्त रहेगी, इनका प्रशिक्षण स्पॉट द्वारा कराया जाएगा। जिला प्रयागराज पुलिस द्वारा अपनी स्वॉट (स्पेशल वीपंस एंड टैक्टिक्स) टीम तैयार की जाएगी जिसे स्पॉट प्रशिक्षित करेगी। मेला क्षेत्र के संयुक्त नियंत्रण कक्ष में कमांडो और क्यूआरटी से संबंधित कमान एक क्षेत्राधिकारी के पास होगी। संयुक्त अभिसूचना ग्रुप भी बनेगा, जिसमें सभी गुप्तचर संस्थाएं त्वरित गति से सूचनाएं शेयर करेंगी।

मेले में आएंगे 15 करोड़ श्रद्धालु

मेले में जन सुविधाओं एवं सुरक्षा के इंतजाम यह मानकर किए जा रहे हैं कि इसमें कम से कम 15 करोड़ लोग आएंगे। अगले साल 15 जनवरी से शुरू हो रहा कुम्भ मेला देश और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होगा। इस मेले में देश और विदेश से श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है।

मेला क्षेत्र लगभग 3200 हेक्टेयर में बसाया गया है जिसे व्यवस्था की दृष्टि से 20 सेक्टरों में बांटा गया है। सुविधा के लिहाज से मेला क्षेत्र चारों दिशाओं से खुला रखा जाएगा। हालांकि इससे मेले की सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती और बढ़ जाती है।

कवरेज के लिए सभी सुविधाएं

प्रयागराज में शुरु हो रहे कुंभ-2019 के कवरेज के लिए प्रदेश सरकार ने देशी विदेशी मीडिया के लिए मुकम्मल इंतजाम किया है। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया के साथ ही इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों के ठहरने के साथ ही रिपोर्टिंग की सुविधाएं विकसित की गई हैं। पत्रकारों को ठहरने के लिए अगल-अलग कॉलोनियां बनाई गई हैं।

शनिवार को दिल्ली में प्रेसवार्ता कर यह जानकारी उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव सूचना, पर्यटन और धर्मार्थ कार्य अवनीश अवस्थी, मुख्यमंत्री के सलाहकार मृत्युंजय कुमार तथा सूचना निदेशक शिशिर ने संयुक्त रूप से दी। श्री अवस्थी ने बताया कि मीडिया सेंटर पूरी तरह वातानुकूलित होने के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रिंटर, फोटोकापी मशीन, टेलिफोन सुविधा, प्रेस कांफ्रेंस हॉल आदि से लैस है।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म भी बनाया गया है जहां पर फेसबुक और ट्वीटर आदि पर पत्रकार काम कर सकेंगे। सेंटर में एग्जीविशन लाउंज, 80 कंप्यूटर चेयर आदि का इंतजाम भी है। 50 लोगों की क्षमता वाले रिसेप्शन रूम और डॉरमेट्री की व्यवस्था है।

यूपी : 60 साल पर रिटायरमेंट का विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों से पास कराना होगा

लखनऊ। राज्य सरकार को रिटायरमेंट की आयु 58 से 60 साल करने के लिए संशोधन विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों से पास कराना होगा। अन्यथा प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों पर 60 के बजाय 58 साल में ही रिटायर होने की तलवार लटकी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर प्रमुख सचिव न्याय और विधि परामर्शी ने अपनी कानूनी राय राज्य सरकार को दे दी है। सूत्रों ने बताया कि प्रमुख सचिव न्याय और विधि परामर्शी द्वारा फैसले के अध्ययन के बाद दी गई कानूनी राय में कहा गया है कि भदोही विकास प्राधिकरण के कर्मचारी की याचिका पर दिया गया फैसला सभी राज्य कर्मियों पर लागू होता है। इसलिए जरूरी है कि कोर्ट के फैसले के अनुपालन में इस तकनीकी गलती को सुधारा जाए। इसके लिए संशोधन विधेयक पास कराना होगा।

वित्त विभाग को संशोधन लाने की जिम्मेदारी दीं

राज्य सरकार को रिटायरमेंट की आयु 58 से 60 साल करने के लिए संशोधन विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों से पास कराना होगा।

सूत्रों का कहना है कि इस तकनीकी गलती को सुधारने के लिए संशोधन लाने की जिम्मेदारी वित्त विभाग को सौंपी गई है। खास बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 58 साल ही मान्य है। क्योंकि मात्र एक अधिसूचना जारी करके रिटायरमेंट की आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई। जबकि रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने वाला मूल नियम 56 विधायी नियम है। विधायी नियम में संशोधन विधानसभा से पास किए बिना मान्य नहीं होगा। इसलिए इस समय रिटायरमेंट की आयु 58 साल ही मान्य है, 60 साल नहीं। इस फैसले के बाद हाईकोर्ट के फैसले की प्रति मिलने के बाद अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंहल ने इस फैसले के अध्ययन के बाद न्याय विभाग से कानूनी राय मांगी थी।

राम मंदिर पर बोले मनोज सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनेगा मंदिर

लखनऊ। केंद्रीय रेल व संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने कहा है अयोध्या में राम मंदिर (Ram Mandir) सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनेगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता चाहती है कि अयोध्या में राम मंदिर बने। बीजेपी ने इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल कर रखा है। उन्होंने लखनऊ के सिटी मांटेसरी स्कूल ऑडिटोरियम में आयोजित गाजीपुर समागम के बाद कही। वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता सुरेश 'भैयाजी जोशी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के अपने वादे को पूरा नहीं करने को लेकर रविवार को भाजपा पर परोक्ष हमला करते हुए केंद्र सरकार से राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग की। पत्रकारों से बातचीत में सिन्हा ने कहा, बीजेपी राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगी। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनेगा। विपक्षी दल इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पिछले चुनाव में ही राम मंदिर का मुद्दा शामिल किया था और यह आज भी कायम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी के पक्ष में अच्छा परिणाम आएगा। एग्जिट पोल को लेकर चल रही चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद रिजल्ट ही देखा जाए। उधर, दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की एक रैली में बोलते हुए आरएसएस के सरकार्यवाह ने कहा, ''जो आज सत्ता में हैं, उन्होंने राम मंदिर बनाने का वादा किया था।

समाज कल्याण विभाग के दो हजार पदों पर भर्ती के लिए 14 लाख दावेदार

लखनऊ एजेंसी। यूपी में एक अदद सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों की कतार काफी लंबी है। यही वजह है कि एक-एक पद के लिए सैकड़ों दावेदार आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समाज कल्याण विभाग के 1953 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा तो 14.33 लाख से अधिक दावेदार सामने आ गए। आयोग आवेदकों की इतनी बड़ी संख्या देखकर शासन से इसके लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराने की अनुमति मांगने पर विचार कर रहा है। आवेदकों की संख्या देखकर होश उड़े: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समाज कल्याण विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527, ग्राम विकास अधिकारी के 362 और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 पदों के लिए मई में विज्ञापन निकाला और 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिया। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों की संख्या देखकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के होश उड़ हुए हैं।

स्क्रीनिंग परीक्षा पर विचार:

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आवेदकों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए पहले स्क्रीनिंग परीक्षा कराने पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि आयोग इसके लिए जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजने पर विचार कर रहा है। शासन से अनुमति मिलने के बाद ही स्क्रीनिंग परीक्षा पर फैसला होगा। आयोग का मानना है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में योग्य आवेदक ही बचेंगे । राज्य सरकार ने अभी हाल ही में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है।

परीक्षा 22 व 23 को कराने की तैयारी

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हालांकि 22-23 दिसंबर को भर्ती परीक्षा कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली 10 से 12 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा 3 से 5 बजे होगी। प्रश्नपत्र 300 अंकों का होगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा।

जनाक्रोश रैली: शिवपाल यादव ने कहा- दंगा भड़काना चाहती है भाजपा

लखनऊ, एजेंसी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (Pragatisheel Samajwadi Party) के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने जनाक्रोश रैली में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा ने देश को कमजोर किया है। हम भाजपा को देश और प्रदेश से हटाएंगे। हम शांति और भाईचारा चाहते हैं लेकिन सांप्रदायिक लोग दंगे भड़काना चाहते हैं। शिवपाल ने कहा कि साल 1992 में भाजपा सरकार द्वारा सुरक्षा की गारंटी का हलफनामा देने के बावजूद बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। वह देश में फिर से वही आग फैलाना चाहती है। आज लोग मुसलमान का नाम लेने में घबराने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली 25 नवंबर को अयोध्या में 'धर्म सभा' के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर निकल पड़े थे कि हम अयोध्या में दंगा नहीं होने देंगे। शिवपाल ने आगे कहा कि वर्तमान की बेईमान, निकम्मी और झूठी सरकार को हटाने की आवश्यकता है। हम और नेता जी (मुलायम सिंह यादव) मुसलमानों के साथ खड़े हैं। हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भी देना चाहते हैं। वादा करते हैं कि हम पुरानी पेंशन दिलाने का काम करेंगे।

संपादकीय

आमदनी बढ़ाएगा निर्यात

सरकार के मुखिया नरेन्द्र मोदी ने स्वयं देश से यह वायदा किया हुआ है कि वह 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इस दृष्टि से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय का नाम पर बदलकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया ताकि इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत हो सके। चूंकि कृषि मूलत- राज्यों का विषय है, इसलिए केंद्र की कदम उठाने की सीमाएं भी हैं। जाहिर है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बनाना एकमात्र उपाय होता है। किंतु कुछ कदम हैं, जिनका निर्णय केंद्र ही कर सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि क्षेत्र का निर्यात 2022 तक दोगुना कर 60 अरब डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य ऐसा ही है। राज्य चाहें भी तो निर्यात की दिशा में अपनी ओर से कदम उठाना कठिन है। इस समय कृषि निर्यात 37 अरब डॉलर है। वस्तुत- अगर किसानों की आय बढ़ानी है तो बहुआयामी कदम उठाने होंगे। इसमें निर्यात की बढ़ोतरी भी एक प्रमुख कदम हो सकता है। हमारे देश में कई बार आंतरिक संकट और परेशानियों को देखते हुए कई बार अनेक कृषि उत्पादों के निर्यात पर रोक लगानी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे पैदावार हो सकते हैं, जिनका पैदावार निर्यात के उद्देश्य से ही किया जाए। खबरों के मुताबिक चाय, काफी, चावल और अन्य जिंसों के निर्यात को बढ़ावा देना है। जाहिर है, इनकी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को प्रोत्साहन देना होगा। भारत में चावल की कुछ ऐसी किस्में हैं, जिनकी विश्व बाजार में मांग हैं। उनको ध्यान में रखकर किसानों को खेती करने को लिए हर तरह का प्रोत्साहन देना होगा। इसके लिए कई पहलुओं पर भी काम करना होगा। इसमें ढांचागत सुविधाओं का आधुनिकीकरण, उत्पादों का मानकीकरण, नियमन को बेहतर बनाना, बिना सोचे फैसलों पर अंकुश और शोध एवं विकास गतिविधियों पर ध्यान देना जरूरी है। वैसे इन पहलुओं के विकास से भारत में कृषि को ऐसा ढांचा उपलब्ध हो सकेगा, जिससे किसान स्वयं लाभान्वित होंगे। हमारे यहां जैविक उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह भी निर्यात के रास्ते की बाधा थी। इसे हटाने की घोषणा कर दी है। किंतु ध्यान रखना होगा कि अत्यधिक आय की चाहत में ज्यादातर जैविक पैदावार विदेश ही न चले जाएं। इसलिए जैविक पैदावार का विस्तार करने के मिशन को काफी आगे ले जाने की आवश्यकता है।

डॉक्टरों पर निगाहें

हिमाचल की जनता के लिए फिलहाल महंगी दवाओं से कुछ राहत की उम्मीदें जगी हैं। सरकार ने डॉक्टरों को सस्ती जेनेरिक दवाएं देने के लिए अपने नियमों में परिवर्तन किए हैं। वर्ष के पूर्वार्ध में ही सरकार ने डॉक्टरों को महंगी ब्रांड वाली दवाओं की अपेक्षा उसी रसायन की जेनेरिक दवाएं देने का निर्देश दिया था। साथ ही यह कि यदि वे कुछ महंगी दवाएं रोगियों को लिख रहे हैं तो उनका स्पष्टीकरण उन्हें लिखित में देना होगा। सरकार ने सरकारी डॉक्टरों को पर्चों की कार्बन कॉपी साथ में रखने की और उन्हें सरकारी कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया था। बाद में लेखा पुनरीक्षण में पाया गया कि लगभग 400 डॉक्टरों ने जेनेरिक दवाओं की अपेक्षा फार्मा कंपनी द्वारा प्रायोजित महंगी दवाएं ही लिखीं। उन पर कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टरों और बड़ी फार्मा कंपनियों की जुगलबंदी को बंद करने के लिए सरकार को अभी कई कदम आगे चलना है। सरकार को इससे संबंधित एक विधेयक लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि जेनेरिक दवाएं सभी स्थानों पर सुविधापूर्वक मिल जाएं और उनमें प्रयोग किए गए रसायनों की उचित गुणवत्ता की जांच की जाए। साथ ही हर गरीब को यह सुविधा व सूचना प्रदान की जाए कि सस्ती जेनेरिक दवाएं सभी स्थानों और सभी लोगों की पहुंच में उपलब्ध होंगी।

दरअसल, हालत यह है कि जिन दवाओं की कीमत फार्मा कंपनियां 8 रुपये तय करती हैं, जेनेरिक दवाओं में वे एक रुपये के मूल्य पर उपलब्ध हैं। आखिर जनता दवाओं की 8 गुनी कीमत क्यों दे। मालूम हो कि जेनेरिक दवाएं चलन में फिसड्डी क्यों हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कई निर्माताओं की दवाएं कई क्वालिटी टेस्ट से बच निकलती हैं, जिसका फायदा फार्मा कंपनियों की दवाएं उठाती हैं। जेनेरिक दवाओं की बाजार में अनुपलब्धता भी कारण है। सरकार सुनिश्चित करे कि जेनेरिक दवाओं के जांच मापदंडों से कोई भी दवा बचने न पाए। इनकी उपलब्धता आम आदमी तक आसानी से हो।

ओशो

स्वतंत्रता

हो जन्म में ज्ञान की यात्रा पूरी हो गई हो तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो एक जन्म और ले सके और चाहे तो न ले। बिल्कुल स्वतंत्रता की स्थिति है। सच तो यह है कि वही एक जन्म स्वतंत्रता से लिया गया होता है। अन्यथा कोई जन्म स्वतंत्रता से नहीं है। चुनाव नहीं है बाकी जन्मों में। बाकी जन्म तो वासना के पाश में बहुत मजबूरी में लेने पड़े हैं। जैसे धकाए गए हैं, या खींचे गए हैं या दोनों ही बातें एक साथ हुई हैं। धकियाए गए हैं पिछले कर्मो से, खींचे गए हैं आगे की आकांक्षाओं से। तो हमारा जन्म साधारणत- बिल्कुल परतंत्र घटना है। उसमें चुनाव का मौका नहीं है। सचेतन रूप से हम चुनते नहीं कि हम जन्म लें। सचेतन रूप से सिर्फ एक ही मौका आता है चुनने का। वह तब आता है, जब व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह जान लेता है। वह घटना घट चुकी होती है, जिसके आगे पाने को कुछ नहीं होता। ऐसा क्षण आ जाता है जब व्यक्ति कह सकता है कि अब मेरे लिए कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कोई वासना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं न पाऊं तो मेरी कोई पीड़ा है। यह बहुत ही शिखर का क्षण है-''पीक।' इस शिखर पर ही पहली दफा स्वतंत्रता मिलती है। यह मजे की बात है और जीवन के रहस्यों में से एक कि जो चाहेंगे स्वतंत्र हों, वे स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं और जिसकी अब कोई चाह नहीं रही, वे स्वतंत्र हो जाते हैं। जो चाहते हैं यहां जन्म ले लें, वहां जन्म ले लें, उनके लिए कोई उपाय नहीं है। और जो इस स्थिति में हैं कि कहीं जन्म लेने का कोई सवाल न रहा, इस सुविधा में हैं कि चाहे तो कहीं ले लें। लेकिन यह भी एक ही जन्म के लिए संभव है। इसलिए नहीं कि एक जन्म के बाद उसे स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी जन्म लेने की। स्वतंत्रता सदा होगी। लेकिन एक जन्म के बाद इसके उपयोग का भाव खो जाएगा। स्वतंत्रता मिलते ही, इस जन्म में यदि आपको घटना घट गई परम अनुभव की, तो स्वतंत्रता तो मिल गई। लेकिन जैसा सदा होता है, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही स्वतंत्रता के उपयोग की जो भाव-दशा है, वह एकदम नहीं खो जाएगी। उसका उपयोग किया जा सकता है। जो बहुत गहरे जानते हैं, वे कहेंगे, यह भी एक बंधन है। इसलिए जैनों ने इसे तीर्थकर-गोत्रबंध नाम दिया। यह आखिरी बंधन स्वतंत्रता का बंधन है। इसका भी उपयोग कर लेने का मन है। वह भी मन ही है। इसलिए सिद्ध तो बहुत होते हैं, तीर्थकर सभी नहीं होते।

यह राजधर्म निभाने का समय है

हरिमोहन मिश्र

बुलंदशहर मगर उलझन ऐसी कि कुछ भी बुलंद नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस जिले के मुख्यालय से करीब चालीस किमी. दूर स्याना थाने में भीड़ की हिंसा, आगजनी और पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक अमित नाम के शख्स की मौत को सारी दुनिया देख चुकी है। तमाम वीडियो भी समय-समय पर सामने आ चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक शायद तय नहीं कर पा रही है कि उसे करना क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी उसे साजिश करार देते हैं, तो कभी उन्हें वह एक दुर्घटना लगने लगती है। वारदात की तहकीकात के लिए बनाई गई एसआइटी के अगुआ डीआइजी कहते हैं कि पहले कथित तौर पर गाय के कंकाल मिलने की जांच की जाएगी। उनके लिए वारदात में दो लोगों की मौत मानो गौण घटना है। जनाक्रोश और चारों तरफ मचे हंगामे के बाद शायद पुलिस कुछ हरकत में आई और अब एक फौजी की तलाश रही है जबकि मुख्य आरोपितों के पक्ष में सोशल मीडिया पर अभियान चल पड़ा है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? क्या इससे हुड़दंगियों को शह नहीं मिलेगी? पुलिस का मनोबल नहीं गिरेगा?यह सवाल इसलिए भी अहम है कि देश के दूसरे खासकर अशांत इलाकों में पुलिसिया कार्रवाइयों में कथित अनियमितताओं की आलोचना की जाती है, तो फौरन ये चर्चाएं गरम हो जाती हैं कि इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा। यहां तक कह दिया जाता है कि ये आलोचनाएं देश के हित में नहीं हैं, और ऐसा करने वाले राष्ट्रद्रोही या अर्बन नक्सल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह भी दावा है कि उनके राज में कोई मॉब लिंचिंग या भीड़ की हिंसा नहीं हुई। लेकिन तय तो कुछ और ही गवाही देते हैं। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद पुलिस वालों के खिलाफ हुड़दंगई की ही जरा इन वारदात पर गौर कीजिए।15 मार्च, 2017 को मेरठ में दुल्हैंडी पर हुड़दंग मचा रहे दो लोगों को सिविल लाइंस पुलिस पकड़कर लाई। उन्हें हवालात में बंद कर दिया। भाजपाई थाने में पुलिस को धमका कर आरोपितों को हवालात से छुड़ा ले गए। एक मई, 2017 को गोरखपुर जिले के चिलुआताल थाना क्षेत्र में भाजपा के सदर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल की फटकार पर सीओ चारू के आंसू निकल आए थे। 24 जून, 2017 को बुलंदशहर जिले की सीओ (स्याना) श्रेष्ठा ठाकुर के एक जिला पंचायत सदस्या के पति के वाहन का चालान काटने पर भाजपा नेताओं ने सीओ ऑफिस पर जमकर हंगामा किया था। पुलिस जब आरोपित को कोर्ट लेकर पहुंची तो उस पर धावा बोल कर आरोपित को छुड़ा लिया गया था। तीखी नोकझोंक के बाद करीब आधा घंटे बाद प्रमोद लोधी को पुलिस को सौंपा गया। 13 दिसम्बर, 2017 को बाराबंकी की सांसद प्रियंका सिंह रावत ने ट्रेनी आईएएस अजय द्विवेदी से कहा कि जीना मुश्किल कर दूंगी। अवैध कब्जा हटाने के अभियान के दौरान सांसद प्रियंका सिंह रावत ने अभियान रोक दिया था। कहने की जरूरत नहीं है कि अवैध कब्जे का आरोप भाजपा के एक स्थानीय नेता पर ही लगा था। बाइस अगस्त, 2018 लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू का पुतला फूंकने को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खासी झड़प हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। मामले में लखनऊ एसएसपी ने इंस्पेक्टर हजरतगंज को लाइन हाजिर कर दिया। बीस अक्टूबर, 2018 को मेरठ में भाजपा के एक पार्षद ने एक दरोगा को अपने रेस्तरां में पीट दिया था। भाजपा नेताओं के भारी दबाव के बावजूद पुलिस ने पार्षद के खिलाफ मुकदमा कर जेल भेज दिया, लेकिन जेल से रिहाई के दौरान समर्थकों ने चलती कार से फायरिंग कर सनसनी फैला दी थी।अगर याद किया जाए तो भाजपा नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठनों की हुड़दंगई की और भी मिसालें याद आ जाएंगी। गाय को लेकर दलित उत्पीड़न की घटनाएं भी कम नहीं हुई हैं। फिर सहारनपुर में जाति झड़प भी याद की जा सकती है, जिसमें भीम आर्मी के सुपीमो चंद्रशेखर आजाद रावण को लंबे समय तक रासुका में बंद रखा गया। ऐसा नहीं है कि राज्य में इसके पहले की सरकारों के दौरान अपराध या सत्ताधारी पार्टी की हुड़दंगई की वारदात नहीं हुई हैं। लेकिन भाजपा या एनडीए सरकार का चुनावों में एक बड़ा वादा राज्य को अपराध मुक्त करना भी था। राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर एनकाउंटरों का आदेश दिया। एनकाउंटरों की छड़ी भी लग गई। जिनकी पुष्टि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट देख लेने भर से हो जाती है। रिपोर्ट को देखने लेने भर से योगी सरकार की एनकाउंटर नीति की कई नहीं, बल्कि ढेरों शिकायतें मिल जाएंगी। विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पाटी (बसपा) की ओर से ये आरोप भी उछले कि सरकार उनके लोगों को निशाना बना रही है। और जब-जब एनकाउंटर नीति की आलोचनाएं हुई तो सरकार की ओर से कहा गया कि अपराधी तत्वों का बचाव और पुलिस का मनोबल गिराने की कोशिश हो रही है।इसलिए क्या बुलंदशहर मामले में भी पुलिस का मनोबल बढ़ाने या कम से कम न्याय के खातिर ही अपराधियों को फौरन गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था? लेकिन इसके बदले हुआ यह कि राज्य सरकार की ओर से जारी पहली प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस वाले के मारे जाने का जिक्र तक नहीं था। यही नहीं, उसमें साजिश का सूत्र सीधे सरकार के शीर्ष से तलाशा जा रहा था। साजिश का सूत्र जब प्रबल नहीं हुआ तो दुर्घटना बताया जाने लगा। अब घटना के लिए पुलिस की लापरवाही को दोषी बताकर जिले के एसएसपी, इलाके के सीओ और थानाध्यक्ष को बदल दिया गया है। दरअसल, साजिश के सूत्र की तलाश में यह फैलाने की कोशिश हुई कि घटनास्थल स्याना से करीब चालीस किमी दूर बुलंदशहर में तबलीगी समाज की बैठक चल रही थी, जिसमें घटना का कोई सूत्र हो सकता है। ये अटकलें भी उछाली गई कि वहां लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी। लगता है कि ये अटकलें इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का हिस्सा थीं। इसी से कुछ हलकों से उठ रही इस शंका पर भी नजर जाती है कि इसका मकसद राजस्थान विधानसभा चुनावों को प्रभावित करना था। ये शंकाएं उसी तरह बेमानी हो सकती हैं, जैसे दूसरी ओर से उठ रही अटकलें हैं, या थीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या किसी ऐसी घटना को दुर्घटना बताई जा सकती है, जिसमें भीड़ थाने पर हमला करती, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले करती दिखती हो और जिसमें दो लोगों की मौत हो गई हो? क्या संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को ऐसा बयान देना चाहिए जिससे हुड़दंगियों को शह मिले। यहां आप याद करेंगे तो विपक्ष में रहते भाजपा नेताओं के पूर्व सरकारों या सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के ऐसे बयानों की घोर आलोचनाएं याद आ जाएंगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में कई वारदात पर भाजपा नेता तृणमूल कार्यकर्ताओं की हुड़दंगई का मामला जोर-शोर से उठाते रहे हैं। ये सब बातें याद दिलाने का यहां मकसद यही है कि कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो एकपक्षीय बातों से परहेज करना ही होगा और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वह हिदायत याद रखनी होगी कि राजधर्म अपनाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने यह बात 2002 में गुजरात दंगों के संदर्भ में कही थी। अगर राजधर्म नहीं पालन किया गया तो उसके भीषण नतीजे क्या होते हैं यह देश 2002 में गुजरात में ही नहीं, दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों में भी देख चुका है। इसलिए अब राजधर्म पालन करने की सीख उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को भी दी जानी चाहिए।

> बड़ा सवाल यह है कि सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या किसी ऐसी घटना को ''दुर्घटना' बताई जा सकती है, जिसमें भीड़ थाने पर हमला करती, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले करती दिखती हो और जिसमें दो लोगों की मौत हो गई हो? क्या संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को ऐसा बयान देना चाहिए जिससे हुड़दंगियों को शह मिले। यहां आप याद करेंगे तो विपक्ष में रहते भाजपा नेताओं के पूर्व सरकारों या सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के ऐसे बयानों की घोर आलोचनाएं याद आ जाएंगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में कई वारदात पर भाजपा नेता तृणमूल कार्यकर्ताओं की हुड़दंगई का मामला जोर-शोर से उठाते रहे हैं
>
> ११

वैश्विकी

भारत की आलोचना सही

डॉ. दिलीप चौबे

यह दुखद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा में कोई निर्णय नहीं लिया गया। अगर चर्चा हो, उसमें बातें रखी जाएं तथा कोई कार्रवाई योजना बने ही नहीं या कम से कम कुछ विरोधी प्रस्ताव तक पारित न हो तो इसका कोई अर्थ नहीं है। भारत ने इस पर क्षोभ प्रकट किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर एनम गंभीर ने विश्व संस्था के लिए जिस तरह के कड़े वक्तव्य का इस्तेमाल किया है, वह बिल्कुल स्वाभाविक है। भारत ने यह साफ कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ को तालिबान के नये नेताओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था। यह बिल्कुल उचित मांग थी। नये तालिबानी नेताओं ने एक ओर से शांति के लिए कतर स्थित अपने कार्यालय के माध्यम से बातचीत के प्रति हामी भरी पर दूसरी ओर वे लगातार हमले भी कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह के अंदर ही उनके हमलों में 60 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है। जिस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतिम चर्चा थी, उसी दिन अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत हेरात में सेना के एक शिविर पर देर रात तालिबान आतंकवादियों ने भीषण हमला कर दिया। इस भीषण हमले में में तत्काल चौदह के करीब सैनिकों के मारे जाने की खबर आई। तालिबान आतंकवादियों की संख्या सैकड़ों में थी। हालांकि हमले में कुछ आतंकवादी भी मारे गए, लेकिन वे कई सैनिकों को उनके हथियारों सहित कब्जे में लेकर अपने साथ ले जाने में सफल रहे। यह शांति की चाहत रखने वाले किसी संगठन का रवैया तो नहीं हो सकता। तालिबान के कुछ पुराने नेताओं पर तो प्रतिबंध लगा हुआ है, पर पता नहीं यह धारणा कैसे बना दी गई कि तालिबान के अंदर जो नया वर्ग आया है, वह शायद किसी समझौते पर पहुंच कर अफगानिस्तान में शांति का वाहक बन जाए। भारत ने मॉस्को वार्ता में गैर-सरकारी स्तर पर अपने दो पूर्व राजनयिकों को अवश्य भेजा, लेकिन वह केवल इसलिए कि अफगानिस्तान की किसी भी वार्ता से बाहर न हो जाएं। चूंकि रूस के साथ वहां चीन और पाकिस्तान सरकारी स्तर पर शामिल थे, इसलिए भारत उससे बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। इस कारण भारत ने अंत में गैर-सरकारी स्तर पर भागीदारी का निर्णय लिया किंतु भारत कभी भी आतंकवाद पर किसी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं रहा। इसलिए भारत बार-बार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आतंकवाद पर पेश प्रस्ताव को पारित करने के लिए जोर दे रहा है ताकि आतंकवाद की एक परिभाषा तय हो और यह भी तय हो कि कौन आतंकवादी हैं, और इस प्रकार उन्हें औपचारिक रूप से चिह्नित करके उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। किंतु दुनिया के कई देश कुछ निहित स्वार्थो के कारण इसमें बाधा बन रहे हैं। इसके पारित हो जाने के बाद पाकिस्तान जैसे देश के लिए तो समस्या खासी बढ़ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा में भी पाकिस्तान एक आरोपित की तरह खड़ा था। हालांकि उसके प्रतिनिधि ने तकरे से अपनी रक्षा की, लेकिन भारत ने साफ किया कि अफगानिस्तान में तालिबान के ज्यादातर हमलों के पीछे पाकिस्तान की अहम भूमिका है। अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने इसे ज्यादा मुखर होकर रखा। साफ है कि संयुक्त राष्ट्र को तालिबान के उन आकाओं को प्रतिबंधित करना चाहिए था। ऐसा लगता है कि कुछ देश कहीं जाने-आने की इनकी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं। यह दुनिया के लिए तो खतरनाक है ही, अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के मार्ग की बहुत बड़ी बाधा भी है। कहना न होगा कि आपने इनको प्रतिबंधित नहीं किया तो दूसरे देशों में इनको पकड़ना संभव नहीं होगा और ये जहां रहेंगे, वहीं से हमलों को नियोजित करते रहेंगे। ऐसे में अफगानिस्तान की शांति दूर की कौड़ी ही रह जाएगी। आज भी अफगानिस्तान के आधा से ज्यादा क्षेत्र तालिबानों के प्रभुत्व में है। इसको खत्म करना दुनिया की जिम्मेवारी है। वहां आईएसआईएस भी खड़ी हो गई है। सीरिया और इराक से उनके पांव उखड़ गए पर वे उस विचार को लेकर अफगानिस्तान में सक्रिय हो चुके हैं। आईएसआईएस से सुरक्षा बलों के संघर्ष के कारण भारी संख्या में ग्रामीण दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर हैं। दोहरे रवैये से अफगानिस्तान का ही नहीं, दुनिया से आतंकवाद का अंत नहीं हो सकता। भारत का यह पक्ष ठीक है कि आतंकवाद के प्रति सभी को बिल्कुल स्पष्ट रवैया अपनाना होगा।

बतंगड़ बेतुक

बलिहारी जनता तू चुनाव हारी

विभांशु दिव्याल

उत्तर-मध्य भारत से लेकर दक्षिण के तेलंगाना तक के चुनावी प्रचार प्रेत मतदायी अनुष्ठान के यथाविधि संपन्न हो जाने के बाद फिलवक्त थम गये हैं। अब आप कह सकते हैं कि जुबानें जिस तरह गंद उगल रही थीं, झूठ और लफ्फाजी पर जिस तरह सच का मुलम्मा चढ़ाया जा रहा था, जिस तरह कहीं हिंदू-मुसलमान और कहीं हिंदू-हिंदू खेला जा रहा था, जिस तरह राजनीतिक वानर-भालू हुमक-हुमककर श्रीराम के नये-नये रूप-विरूप गढ़ रहे थे, जिस तरह भाषायी शुचिताओं का चीरहरण हो रहा था, और जिस तरह व्यावहारिक मर्यादाओं को सरेआम नंगा किया जा रहा था, चुनाव के नाम पर जो घृणोन्माद पैदा किया जा रहा था, वह आप जैसे धीर-गंभीर की सहनशक्ति से परे था। घनघोर प्रतिस्पर्धा हो रही थी कि कोई भी आयं-बायं, अंट-शंट बकने में किसी से पीछे न छूट जाए। आप मान सकते हैं कि युद्धरत सांड़ों के बीच मीडिया हर उस बयान और हर उस घटना को लाल कपड़े की तरह लहरा रहा था जो उत्तेजित करती हो, दिमाग के दरवाजे बंद करती हो और एक दूसरे की खाल खुरचने के लिए सींगों को पैना करती हो। आप सोच सकते हैं कि प्रचार की गाड़ी के पहिए तो थोड़ी देर के लिए थमे, लेकिन अपने पीछे इतना जहरीला धुंआ छोड़ गए, वातावरण को इतना प्रदूषित कर गए कि सांस लेने में स्वच्छ हवाओं की चीखें निकल जाएं। आप पूछ सकते हैं कि समूचे चुनाव अभियान में दीन-हीन जनता के दुख-दर्द कहां थे, रोजमर्रा की समस्याएं कहां थीं? आपके इन सवालों के जवाब या तो अली जाने या फिर बजरंग बली। और आपका सोचना-मानना-लगना सब कूड़ेदान की तरफ दरकिनार, वास्तविकता है कि यह हमारे चुनावी लोकतंत्र की एक और सफल छलांग थी, जो चुनाव प्रचार के उच्च मानक स्थापित करके पूरी हुई।अब जब चुनाव हो चुके हैं, तो महान नेताओं की महान वाणियां सुन लीजिए, लगता ही नहीं इनमें से कोई भी हारेगा। जिसकी जमानत जब्त होनी है, विजयनाद कर रहा है, और जिसे जनता जुतिया चुकी है, राजगद्दी पर दावा ठोक रहा है। जिसकी पहले सरकार थी, विशाल बहुमत से दुबारा सरकार बनाने की बात कह रहा है, और जिसे वर्षो से सत्ता के दरवाजे देखने को नहीं मिले वह भी दावेदारी पेश कर रहा है। एग्जिट पोल जिसे हारा हुआ बता रहा है, एग्जिट पोल को गलत ठहरा रहा है। एग्जिट पोल जिसे जीता बता रहा है, अपनी पीठ थपथपा रहा है। जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते, मीडिया दावों और प्रतिदावों की कुश्तियां करवाता रहेगा, ''सभ्य' और ''सुसंस्कृत' वक्ताओं-प्रवक्ताओं की चोंचें लड़वाता रहेगा, जुबानों की बेलगाम जूतमपैजार करवाता रहेगा और जिनसे ये जूतमपैजार ज्यादा मारक और दर्शक-लुभावनी बनती हो वे जहरबुझी चुनिंदा बाइटें और चुनिंदा उत्तेजक फुटेज भी दिखाता रहेगा। मीडिया के उछल बच्चे टीआरपी की टोपी पहनकर ले मार-दे मार करते रहेंगे। वे कसम खाकर बैठते हैं कि न किसी सही-समझदार, शांत-सरल व्यक्ति को अखाड़े में आमंत्रित करेंगे और न किसी भी बहस-विमर्श को तार्किक तरीके से आगे बढ़ने देंगे। भले ही लोकतंत्र के खंबे चरमरा रहे हों लेकिन वे चौथा खंबा होने के अपने मलखंब पर इसी तरह ऊपर-नीचे होते रहेंगे। दर्शक अपनी रुचि-अरुचि, लगाव-विलगाव, जात-कुजात, भक्ति-विरक्ति, धर्म-मजहब के पूर्वाग्रह लेकर इनका आनंद लेता रहेगा। जिसमें उसकी विनयावनत आस्था होगी उस पर चहचहाते हुए ताली पीटेगा और जिसमें अनास्था होगी उस पर खोखियाएगा और उसे गुस्से से गरियाएगा। यह देखकर आपकी इच्छा बाल नोंचने की हो तो बेझिझक नोंचते रहिए। उमड़ ज्यादा हो तो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सऐप पर अपने दो-चार भड़ासिया कमेंट डालते रहिए। लेकिन इससे कथित मुख्यधारा के मीडिया के चाल-चरित्र में न कोई बदलाव आएगा और न हमारे महान नेताओं के चाल-चरित्र में।आपके जहन में कुछ दूसरी प्रजाति के बेसिर-पैर के सवाल भी कुलबुला सकते हैं कि जहां भाजपा सत्ता में है, वहां कांग्रेस सत्ता में आ गई तो जनता पर कौन-सा दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा या कौन-सा सुख का समुद्र उमड़ पड़ेगा। पहले वाले भी संविधान की शपथ लेकर आए थे, नये वाले भी संविधान की शपथ लेकर आएंगे। पहले वाले भी जनता की दुहाई से जनता का वोट लेकर आए थे, नये वाले भी जनता की दुहाई के साथ जनता का वोट लेकर सत्ता में आएंगे। हां, भाजपा और उसके भक्त-देशभक्त शोकाकुल हो जाएंगे और कांग्रेस तथा उसके धर्मनिरपेक्ष नवहिंदू हर्षातिरेक में डूब जाएंगे। एक तरफ हार का ठीकरा फोड़ने के लिए सर तलाशे जाएंगे तो दूसरी तरफ जीत का श्रेय लेने के लिए सीने फुलाए जाएंगे। बहुत से पुराने खेमे उखड़ जाएंगे, बहुत से नये तंबू सज जाएंगे। नये तंबुओं में नये चेहरे नजर आएंगे और वे अपनी पुरानी रीति-नीति के अनुसार अपनी नई दुकानदारी सजाएंगे। बेदखल हुए, उखड़े हुए दलदलिए राजनीतिबाज लोकतंत्र के स्थापित पुराने मानकों का अनुपालन करते हुए मातम के मोड से निकल कर नई गोलबंदियां सजाएंगे। अब तक जो काम वे कर रहे थे, अब ये करेंगे। सरकारी निकम्मे-नाकारापन और असफलता के आरोप पहले वे लगा रहे थे, अब ये लगाएंगे। किसानों, बेरोजगारों, व्यापारियों का रोना पहले वे रो रहे थे, अब ये रोएंगे। रही जनता की बात तो वह अब भी वहीं रहेगी जहां पहले थी, इस और उसके बीच झूलती हुई, निरंतर मूढ़ बनती हुई, लगातार मूर्ख बनाई जाती हुई। जनता हर चुनाव हार रही है।

सार समाचार

ईरान: पुलिस पर आत्मघाती हमला, 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार

तेहरान। ईरान पुलिस ने रविवार को कहा कि दक्षिणपूर्वी ईरान में पुलिस पर हुए आत्मघाती हमले के संबंध में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस हमले में दो पुलिस अधिकारियों की मौत हुई थी. गुरुवार को हुए हमले की जेहादी अलगाववादी संगठन अंसर अल फुरकान ने जिम्मेदारी ली थी. बंदरगाह शहर चाबहार के थाने में विस्फोटक से लदी कार में विस्फोट किया गया था जिसमें करीब 40 लोग घायल हुए थे. अधिकारियों ने इस हमले की जिम्मेदारी के दावे को खारिज किया. 'फार्स' समाचार एजेंसी की खबर के अनुसार, पुलिस प्रमुख हुसैन अश्तरी ने कहा कि इस संबंध में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अंसर अल फुरकान ने शनिवार को अब्दुल्ला अजीज नाम के कथित आत्मघाती हमलावर की तस्वीर जारी की थी.

पाकिस्तान से लौट रही भारतीय महिला की रास्ते में मौत, सड़क रास्ते से लाया गया शव

बाड़मेर। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन थार एक्सप्रेस में पाकिस्तान से भारत लौट रही एक महिला की शनिवार को रास्ते में मौत हो गयी. मृतका राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर जिले की निवासी थी. नाम नहीं छापने की शर्त पर एक प्रर्वतन अधिकारी ने बताया कि महिला का शव पाकिस्तान के खोखरापार रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पाकिस्तान अधिकारियों ने आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद मुनाबाव में नियुक्त भारतीय अधिकारियों को सौंपा. शव के मुनाबाव में आने के बाद भारतीय अधिकारियों ने विशेष अनुमति देते हुए महिला के शव को सड़क मार्ग से मुनाबाव से ही उसके गांव रवाना किया. उन्होंने बताया कि मृतका की शिनाख्त जमीयत पत्नी कायम खान उम्र 73 वर्ष निवासी मण्डाई जिला जैसलमेर के रूप में की गयी. जमीयत बीस दिन पहले पाकिस्तान में रहने वाली अपनी बेटी से मिलने गयी थी. पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद जमीयत अपने बेटे हलीम और अन्य कुछ रिश्तेदारों के साथ थार एक्सप्रेस, जो शुक्रवार देर रात पाकिस्तान के कराची से रवाना हुई, से भारत लौट रही थी. शव के मुनाबाव पहुंचने के बाद भारतीय अधिकारियों ने जमीयत के शव को विशेष अनुमति के साथ उसके पुत्र हलीम के साथ सड़क मार्ग से सीधे उसके गांव जैसलमेर के लिए रवाना किया, वहीं शेष रिश्तेदारों को थार एक्सप्रेस में जोधपुर के लिए रवाना किया गया.

खालिदा जिया नहीं लड़ सकेंगी चुनाव, बांग्लादेश चुनाव आयोग ने खारिज की याचिका

ढाका। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की चुनाव लड़ने की याचिका को खारिज कर दिया है. इससे खालिदा की चुनाव लड़ने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. आयोग ने 4-1 के मत से इस याचिका को खारिज कर दिया. मुख्य चुनाव आयुक्त समेत तीन आयुक्तों ने याचिका का विरोध किया जबकि एक आयुक्त ने समर्थन किया. इससे पहले बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने 73 वर्षीय खालिदा को 30 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए यह कहते हुए अयोग्य करार दिया था कि दो साल से ज्यादा कैद की सजा पाए लोग, जिनकी याचिका अदालत में लंबित है, चुनाव नहीं लड़ सकते.

पीएम मोदी के आगे झुका चीन, विवाद भूलकर मिलाया हाथ और करने जा रहे साथ में ये काम

बीजिंगः (एजेंसी)।

भारत और चीन आतंकवाद से लड़ने की अपनी क्षमताओं में सुधार लाने और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए, करीब एक साल के अंतराल के बाद मंगलवार को दक्षिण पश्चिम चीनी शहर चेंगदू में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करेंगे. अधिकारियों ने बताया कि अभ्यास का उद्घाटन समारोह 11 दिसम्बर को आयोजित किया जाएगा. चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल रेन गुओकियांग ने पिछले महीने कहा था, कि सातवें भारत-चीन साझा सैन्य अभ्यास 'हैंड इन हैंड' में दोनों तरफ से 100-100 सैनिक हिस्सा लेंगे. अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केन्द्रित होगा. वर्ष 2017 में दोनों देशों के बीच सिक्किम के डोकलाम क्षेत्र में करीब 73 दिन तक गतिरोध चलने के कारण यह अभ्यास करीब एक साल बाद हो रहा है.

चीन के वूहान में इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की अनौपचारिक शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच संबंध पुनः पटरी पर लौटे.कर्नल रेन ने कहा, ''अभ्यास से दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ावा मिलेगा और आतंकवाद से लड़ने की उनकी क्षमताओं में सुधार आएगा.'' उन्होंने बताया कि यह अभ्यास 23 दिसम्बर तक चलेगा.

पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां जी - 20 शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.पीएम मोदी और शी अप्रैल में चीनी शहर वुहान में हुई अपनी अनौपचारिक बैठक के बाद दो बार मिल चुके हैं. वे दोनों जून में चीन के चिंगदाओ में हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन में मिले थे और फिर जुलाई में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनकी मुलाकात हुई थी.

इस तरह की पहल गति को बनाए रखने में मददगार

पीएम मोदी ने शी से कहा कि वह अगले साल एक अनौपचारिक बैठक में उनकी मेजबानी करने की आशा करते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा,'आज की बैठक हमारे संबंधों को मजबूत करने के संदर्भ में एक दिशा प्रदान करने में अहम होगी.' उन्होंने कहा, 'इस तरह की पहल गति को बनाए रखने में मददगार है.' पीएम मोदी ने कहा,'इस मुलाकात के लिए वक्त निकालने को लेकर मैं आपको (राष्ट्रपति शी को) अपनी हार्दिक बधाई देता हूं.% प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों ने पिछले एक साल में लंबे डग भरे हैं.

गौरतलब है कि सिक्किम के डोकलाम सेक्टर में 2017 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच 73 दिनों तक चले गतिरोध के बाद भारत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे. दोनों देशों के बीच संबंधों में जमी बर्फ पिघलने के परिणामस्वरूप वुहान में पीएम मोदी और शी की एक अनौपचारिक बैठक हुई थी, जहां दोनों नेताओं ने विश्वास और तालमेल बनाने के लिए संचार मजबूत करने की खातिर अपनी - अपनी सेनाओं को रणनीतिक दिशानिर्देश जारी करने का फैसला किया था.

मलेशिया में मुस्लिम समुदाय ने निकाली रैली, अपने अधिकार खत्म करने का विरोध

कुआलालंपुर (एजेंसी)।

मलेशिया में हजारों मुस्लिमों ने मलय बहुसंख्यकों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के किसी भी प्रयास के विरोध में शनिवार को यहां बड़ी रैली निकाली. प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के गठबंधन को मई में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद यह पहली बड़ी रैली है. इस रैली को देश की दो सबसे बड़ी विपक्षी मलय पार्टियों का समर्थन था. यह नस्लीय भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्र संधि को अंगीकार करने की सरकार की योजना के विरोध पर केंद्रित थी.

आलोचकों का मानना है कि संधि को अंगीकार करने से मलय समुदाय के लोगों को प्राप्त विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे. हालांकि यह योजना फिलहाल त्याग दी गई है.

दंगों के बाद से शांति

मलेशिया में 1969 में भीषण दंगों के बाद से शांति है. इसके एक वर्ष के बाद मलेशिया ने तरजीही कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत मलय समुदाय के लोगों को रोजगार, शिक्षा, अनुबंध और आवास में विशेषाधिकार दिए गए थे. यह पूरी कवायद अल्पसंख्यक चीनी समुदाय के साथ धन के अंतर को समाप्त करने के लिए थी. तीन करोड़ 20 लाख की आबादी वाले इस देश में मलय समुदाय की संख्या करीब दो तिहाई है. इसके अलावा चीनी और भारतीय लोग बड़ी संख्या में यहां हैं जो अल्पसंख्यक हैं.

शनिवार को हुई यह रैली दूरदराज के इलाके में स्थित एक भारतीय मंदिर में दंगे के बाद 80 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के दो सप्ताह से भी कम समय में हुई है. सरकार ने इस पूरे मामले को भूमि विवाद से जुड़ा मामला बताया और कहा कि यह नस्लीय हिंसा नहीं थी. महातिर का कहना है कि सरकार ने देश में लोकतंत्र के कारण रैली की इजाजत दी है, साथ ही किसी भी प्रकार की अराजकता फैलने के प्रति लोगों को आगाह भी किया. प्रदर्शन में शामिल लोगों में से अनेक ने सफेद टीशर्ट पहनी हुई थीं जिन पर ''रिजेक्ट आईसीईआरडी'' लिखा था. इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र संधि (इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन) से था.

यह मलय लोगों का देश है

प्रदर्शन में शामिल एक छात्र नूरुल कमरयाह ने कहा, ''मेरे लिए आईसीईआरडी खराब है. यह इसलिए खराब है क्योंकि यह मलय लोगों की स्थिति को नीचे लाएगा. यह मलय लोगों का देश है. हम चाहते हैं कि मलय समुदाय के लोग सर्वश्रेष्ठ रहें लेकिन ये लोग क्यों मलय समुदाय के लोगों को चीनी और भारतीयों के बराबर लाना चाहते हैं.''

खशोगी मामले से निपटने के लिए कुशनर ने सऊदी क्राउन प्रिंस को दी सलाह: रिपोर्ट

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिकी मीडिया की खबर के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने सऊदी अरब के वली अहद (क्राउन प्रिंस) मोहम्मद बिन सलमान के साथ पत्रकार जमाल खशोगी की नृशंस हत्या के बाद भी न केवल निजी बातचीत जारी रखी बल्कि इससे निपटने के तरीकों के लेकर भी सलाह-मशविरा दी. न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बातचीत से परिचित सऊदी सूत्र के हवाले से खबर प्रकाशित की है कि इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास के भीतर खशोगी की हत्या के बाद कुशनर ने सलमान को 'इस तूफान से निपटने' के तरीके पर भी सलाह दी.

रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के शुरुआती महीनों से ही पश्चिम एशिया के ट्रंप के सलाहकार कुशनर की निजी और अनौपचारिक बातचीत सलमान से होने लगी थी. यह स्थिति अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए चिंता का विषय था. तीन अमेरिकी पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि कुशनर की यह राजनीतिक अनुभवहीनता उन्हें सऊदी अरब के दांव-पेंच का शिकार बना सकती है. व्हाइट हाउस के तौर-तरीके कठोर करने के प्रयास के तहत नए चीफ ऑफ स्टाफ ने पुराने समय में चली हुई उस परंपरा को फिर से शुरू करने की कोशिश की कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य विदेशी नेताओं के साथ होने वाली सभी बातीचत में हिस्सा लेंगे. व्हाइट हाउस के तीन पूर्व अधिकारियों और सऊदी अरब के शाही दरबार के अधिकारियों द्वारा दो लोगों को दी गई जानकारी के मुताबिक इस प्रतिबंध के बाद भी 37 वर्षीय कुशनर 33 वर्षीय सलमान के साथ अनौपचारिक बातचीत जारी रखे हुए हैं. यहां तक कि ये दोनों लोग एक दूसरे का पहले नाम से संबोधित करते हैं. यह बातचीत दो अक्टूबर को खशोगी की हत्या के बाद भी जारी रही.

पाकिस्तान ने आम लोगों के लिये राष्ट्रपति भवन के दरवाजे खोले

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान सरकार ने कड़ी सुरक्षा वाले आलीशान राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिये खोल दिया। राष्ट्रपति भवन का आधिकारिक नाम ऐवान-ए-सदर है। यह राजधानी के अति सुरक्षा वाले रेड जोन के कांस्टिट्यूशन एवेन्यू में मारगल्ला हिल्स पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन आधुनिक पिरामिड वास्तुकला की शानदार शैली को दर्शाता है। इसके एक ओर प्रधानमंत्री आवास और दूसरी ओर संसद भवन है। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ताहिर खुशनूद ने कहा कि पहचान पत्र दिखाकर आम लोगों को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक भवन में प्रवेश की अनुमति है। इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने चुनावों के दौरान सत्ता में आने पर देश की मुख्य इमारतों को आम लोगों के लिये खोलने का वादा किया था। उसी वादे के तहत यह फैसला किया गया। इस नीति के तहत लाहौर, कराची और पेशावर में गवर्नर हाउस को पहले ही आम लोगों के लिये खोल दिया गया था। सितंबर में लाहौर में गवर्नर हाउस खुलने के पहले ही दिन 4 हजारों लोगों ने इसका दीदार किया था।

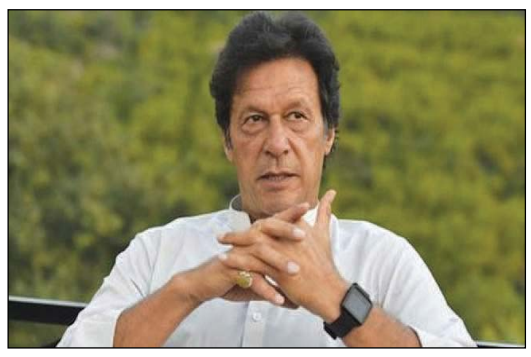

माल्या प्रत्यर्पण केस की सुनवाई के लिए सीबीआई और ईडी की टीम ब्रिटेन रवाना, आज आ सकता है फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)।

बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेकर फरार हुए भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई सोमवार को ब्रिटेन की कोर्ट में हो सकती है. इसके लिए रविवार को सीबीआई और ईडी की संयुक्त टीम सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ए साई मनोहर के नेतृत्व में ब्रिटेन रवाना हो गई है. माना जा रहा है कि कोर्ट माल्या के प्रत्यर्पण के मामले में सोमवार को अपना फैसला सुना सकता है.

ब्रिटेन की कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत के विशेष अनुरोध पर सुनवाई होनी है. बता दें कि सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस?थाना पहले इस केस का नेतृत्व कर रहे थे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए मुंबई की एक अदालत में चल रही कार्यवाही को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर 7 दिसंबर को को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने विजय माल्या की याचिका पर नोटिस जारी किया लेकिन उसने मुंबई की धन शोधन मामले की रोकथाम संबंधी विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.

प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत से लंदन में रह रहे कारोबारी माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया है. इस कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया तो उस पर मुकदमा चलाने वाली एजेन्सी को उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता है.

वहीं भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने बुधवार को कहा कि उनके ब्रिटेन से भारत में प्रत्यर्पण के मामले में कानून अपना काम करेगा लेकिन मैं 'जनता के पैसों' का 100 प्रतिशत भुगतान करने के लिये तैयार हूं.

माल्या प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने दावा कि नेताओं और मीडिया ने उन्हें गलत तरीके से 'डिफॉल्टर' के रूप में पेश किया. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 'मैंने देखा है कि मेरे प्रत्यर्पण के फैसले को लेकर मीडिया में कई चर्चाएं चल रही हैं. यह अलग मामला है और इसमें कानून अपना काम करेगा.' माल्या ने कहा, 'जनता के पैसे सबसे जरूरी चीज है और मैं 100 प्रतिशत पैसे वापस करने की पेशकश कर रहा हूं. मैं बैंकों और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो इस पेशकश को स्वीकार करें.÷ माल्या पर कई बैंकों का 9000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है. यह कर्ज उसकी कंपनी फिंगफिशर एयरलाइंस को दिया गया था.माल्या मार्च 2016 में देश छोड़कर ब्रिटेन चले गये थे.

प्रदर्शनों से उबल रहा फ्रांस, मैक्रों का कुछ पता नहीं

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आगामी 15 दिसम्बर को अफगानिस्तान के दौरे पर जायेंगे। उनकी इस यात्रा का मकसद शीर्ष अफगान नेतृत्व के साथ बातचीत कर युद्ध प्रभावित देश में ''राजनीतिक मेलमिलाप और स्थायी शांति'' लाने की दिशा में प्रयास करना है।

कुरैशी ने काबुल जाने का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रधानमंत्री इमरान खान को लिखे पत्र के बाद किया है। इस पत्र में ट्रम्प ने पाकिस्तान से कहा था कि वह अफगान शांति वार्ता में उनकी मदद करे और तालिबान को बातचीत की मेज पर लाने में सहायता करे ताकि अफगानिस्तान में बीते 17 साल से चल रहे खूनी युद्ध को खत्म किया जा सके।

रेडियो पाकिस्तान के अनुसार, कुरैशी ने शनिवार को मुल्तान में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान की विदेश नीति की मजबूती है जिसकी वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान मामले में सहायता करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगान नेतृत्व वाली और अफगान शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में राजनीतिक सुलह-सहमति और स्थायी शांति पर अफगान नेतृत्व के साथ बातचीत करने के लिए वह 15 दिसंबर को काबुल जाएंगे।

अगस्त में पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ सरकार सत्ता में आने के बाद कुरैशी की काबुल की यह दूसरी यात्रा होगी।समारोह को संबोधित करते हुए कुरैशी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने करतारपुर गलियारे को खोलने का निर्णय सिख तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए किया है। उन्होंने कहा, ''यह कदम पाकिस्तान की ओर से शांति और प्यार का संदेश है।

विमानों में उत्पीड़न के खिलाफ हांगकांग की महिला क्रू मेंबर्स ने चलाया 'मीटू' कैंपेन

हांगकांग (एजेंसी)।

हांगकांग के विमानों के चालक दल की महिला सदस्य अपने साथ विमानों में होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायतों को लेकर 'मीटू' आंदोलन के दौर में मुखर हो रही हैं. हांगकांग के विमान चालक दल की महिला सदस्यों ने बताया कि उन्हें न सिर्फ विमान के यात्री प्रताड़ित करते हैं, बल्कि एयरलाइन के कर्मचारी भी उनका उत्पीड़न करते हैं. उन्होंने कहा कि एयरलाइनों ने सही दिशा में कुछ कदम उठाए हैं लेकिन वह अब भी 'मीटू' के दौर में महत्वपूर्ण कदम उठाने में पीछे हैं.

'टाइट स्कर्ट' पहनने की शिकायत करने की धमकी

हांगकांग कैबिन अटेंडेंट यूनियन का नेतृत्व करने वाली वेनस फंग ने कहा कि एयरलाइनों को अपने कर्मचारियों को उत्पीड़न से कैसे निपटना है, इसके बारे में जरूर बताना चाहिए. फंग का कहना है कि अपने दुखद अनुभवों की वजह से वह यूनियन में शामिल हुई हैं. फंग ने बताया कि एक पायलट ने अभद्र तरीके से उन्हें उस समय छुआ था जब वह इस नौकरी में नयी थीं. उनका कहना है कि घटना के समय कैबिन प्रबंधक ने मामले में हस्तक्षेप करने के बजाय उन्हें ही 'टाइट स्कर्ट' पहनने की शिकायत करने की धमकी दी.

तनुश्री दत्ता-नाना पाटेकर विवाद पर शिल्पा शेट्टी का बयान, जानिए क्या कह दिया

इसके बाद उन्होंने स्कर्ट पहनना ही बंद कर दिया. वह अभी एक यूरोपीय एयरलाइन में काम करती हैं. इस स्थिति को बदलने की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है. यहां तक कि महिला चालक दल के सदस्यों के मेकअप और कपड़ों में भी विकल्प को जोड़ने की मांग बढ़ी है.

जय सरदार जय पाटीदार के नारों के साथ निकाली संकल्प यात्रा

उधना दरवाजा से शुरु हुई संकल्प यात्रा

सूरत। 3 महीने 20 दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा होने पर पास नेता अल्पेश कथीरिया का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर उधना दरवाजा से समाज के लोगों ने संकल्प यात्रा निकाली। इस संकल्प यात्रा में हजारों की संख्या में पाटीदार समाज के लोग शामिल हुए। लाजपोर जेल पर हार्दिक पटेल सहित पाटीदार अनामत आंदोलन के संयोजक अल्पेश कथीरिया के परिवार के लोग सुबह ही पहुंच गए थे।

अहमदाबाद राजद्रोह केश के बाद सूरत राजद्रोह केस तथा हत्या के प्रयास के केस में जमानत मिलने पर अल्पेश कथीरिया को रविवार को लाजपोर जेल से रिहा किया गया। अल्पेश की रिहाई की खबर सुनते ही पाटीदार समाज में हर्ष का माहौल व्याप्त हो गया। जेल से बाहर आते ही अल्पेश के परिवार जनों ने तिलक लगाकर तथा हार पहना कर स्वागत किया। इस बीच लोगों ने जय पाटीदार जय सरदार का नारा लगाया। परिववार जनों द्वारा भव्य स्वागत किए जाने पर अल्पेश भाव विभोर हो गए। जेल से बाहर आने के बाद अल्पेश कथीरिया ने बताया कि 3 महीना जेल में रहने का बाद मुझे बहुंत कुछ सीखने को मिला। अल्पेश ने कहा कि 3 महीने बाद भी समाज के लोगों में किसी प्रकार का उत्साह कम नहीं हुआ है। जिस प्रकार महाराष्ट्रर में मराठा समाज के लोगों ने अपने आंदोलन से सरकार को झुका दिया और सरकार ने उनकी मांगे मान ली। उसी प्रकार गुजरात सरकार भी पाटीदारों को अनामत देने को मजबूर होना पड़ेगा। संकल्प यात्रा के द्वारा पाटीदारों में नई चेतना और जोश का विकास होगा। संकल्प यात्रा उधना से आरंभ होकर रिंग रोड़ होते हुए लाल दरवाजा खाड़ बाजार गरनाला, पोद्धार आर्केड, बेशाली तीन रास्ता उमियाधाम मंदिर, डायमंड सौराष्ट्र पाटीदार समाज की वाड़ी, मानगढ चौक मीनी बाजार पहुंची जहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर हार चढाया गया। उसके बाद खोड़ियार नगर तीन रास्ता, बरोड़ा प्रिस्टेज, हीराबाग सर्कल, श्री रामनगर सोसायटी, रचना सर्कल गायत्री नगर, बूटभवानी, सीतानगर चौकड़ी, पूणागाम बस स्टैड, पूणा तालाब, नालंदा स्कूल, कारगिर चौक, किरण चौक, योगी चौक, बारा सीताराम चौक, बीआरटीएसरोड़, सीमाड़ा नाका, सबजी कोराट पुल, लजामणी चौक होते हुए सुदामा चौक पहुंच कर सम्पन्न हुई। हार्दिक पटेल ने कहा कि जब हम अल्पेश को लेने लाजपोर जेल जा रहा था तो पुलिस ने हमे रोकने का प्रयास किया। पुलिस वालों ने बिना वजह हमारी कार को रोका अऔर गाड़ी की चेंकीग के बहाने काफी देर तक इधर उधर करते रहे। ताकी समय पर हम जेल न पहुंच सके। अल्पेश कथीरिया की रिहाई के बाद हमारी योजना थी कि हम जेल से संकल्पयात्रा निकालना था। परन्तु प्रशासन ने उसकी इजाजत नहीं दी। बाद में पुलिस ने उधना दरवाजा से संकल्प यात्रा निकालने की मंजूरी दी। जिसके बाद उधना दरवाजा से संकल्प यात्रा का आरंभ किया गया। अल्पेश कथीरिया की रिहाई को लोकतंत्र की जीत बताते हुए हार्दिक ने कहा कि अब आंदोलन की कमान अल्पेश संभालेंगे और पाटीदार समाज के युवाओं का मार्ग दर्शन करेंगे।

दक्षिण गुजरात में बढा टंड का असर

सूरत। जम्मू काश्मीर में हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारतमें ठुठिरा देने वाली ठंड पड़ रही है। उत्तर दिशा की और से शहर में आने वाली हवाओं ने समग्र दक्षिण गुजरात में ठंड का ऐहसास करा दिया है। ठंड़ का असर बढने से लोग गर्म कपड़े पहने हुए नजर आने लगे है। साथ ही गर्म कपड़ों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ दिखाई देने लगी है।

रविवार को साल की सबसे अधिक ठंड देखने को मिली। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनसुरा रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया। हवा में नमी की मात्रा 80 प्रतिशत तथा हवा का दबाव 1014.5 मिलीबार दर्ज किया गया। शहर में सुबह से ही उत्तर दिशा की और से 2 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाए चली। नवसारी जिले के मौसम विभाग के अनुसार नवसारी में अधिकत्तम तापमान 32.7 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। जो इस वर्ष इस सीजन का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। वहीं वलसाड़ जिले में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री दर्ज किया गया

उत्तर भारत की और से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण समग्र गुजरात के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिला है।

एपीएमसी के करोड़ों का टैक्स वसूल करने हेतु वोर्ड समिति में प्रस्ताव

कड़ाई के साथ होगी टैक्स की वसूली

सूरत। सामान्य लोगों से टैक्स की पठानी वसूली करने तथा सील मारने की धमकी देने वाले सूरत महानगर पालिका की एपीएमसी मार्केट में करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया चल रहा है। जिसके चलते शनिवार को वार्ड नं. 18, आजंणा-खटोदरा की वार्ड समिति के अध्यक्ष असलम सायकलवाला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें एपीएमसी मार्केट में बकाया करोड़ों रुपये की टैक्स का कड़ाई से वसूलने का प्रस्ताव पास किया गया। इस बोर्ड के अध्यक्ष असलम सायकलवाला, शैलेष रायका, कपिलाबेन पटेल तथा असिस्टेंट कमिश्नर हर्षद किनखाब वाला उपस्थित रहे। बैठक में बोर्ड समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए 28 सुझावों के साथ एपीएमसी मार्केट में करोड़ों रुपयों के टैक्स बकाया का मामला भी शामिल था। लगभग दो करोड़ रुपये के बकाया की रकम वसूलने में साउथ ईस्ट जोन लिंबायत का अकारणी विभाग का लचर रवैया रहा है। सामान्य लोगों की सम्पत्ति पर सील मारकर जिस पर कार्रवाई की जा रही है। यदि इसी प्रकार की कार्रवाई विभाग के अधिकारी एपीएमसी मार्केट में बकाया टैक्स की राशि के वसूली पर दिखाते तो करोड़ों का बकाया नहीं रहता।

भुलाभाई पार्क में स्थित बहुचर माता की मंदिर का प्रागटय दिवस मनाया गया जिसके तहत अन्नकूट दर्शन का आयोजन किया गया।

रघुकुल मार्केट से जयअंबे साड़ी उठी

सूरत। एम्ब्रोडरी जाब वर्क करार के साथ रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट में जयअंबे साड़ी नाम से व्यापार करने वाले व्यापारी ने 11.03 लाख रुपये का जाब वर्क कराकर रकम न चुकाने तथा दुकान बंद करके फरार होने की शिकायत दर्ज कराई गई है।

सलाबतपुरा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार पुणा, जे.टी.नगर निवासी तथा एम्ब्रोडरी का काम करने वाले रघुभाई मुंजाणी ने आरोपी माणेकचन्दर चेतनराम देवासी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस को दिए शिकायत में फरीयादी ने कहा है कि आरोपी ने उसके अलावा अन्य कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। इस तरह आरोपी ने कुल 79,03,607 रुपये का वर्क कराने के बाद बिना भुगतान किए दुकान बंद करके फरार हो गया है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी ह ै। पार्टी उठाने की लगातार बढती घटनाओं ने सूरत के कपड़ा बाजार को एक बार फिर बदनाम कर दिया है। आए दिन बाहर से आने वाले व्यापारियों की जेब कटने की घटनाओं ने बाहर के व्यापारियों का विश्वास खो दिया है। ऐसे में पार्टी उठने की घटना से लोगों को भारी अघात पहुंचा।

योगी चौक एपल स्क्वेयर की पार्कींग में गैस लीकहोने से मची हलचल

सूरत। शनिवार की सुबह पौने ग्यारह बजे के करीब वराछा के योगी चौक के निकट स्थित एपल स्क्वेयर अपार्टमेंट की पार्कींग में गैस लीक होने की सूचना फायर कंट्रोल को मिली। सूचना मिलेत ही फायर ब्रिगेड की टीम लाव लश्कर सहित घटना स्थल पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड विभाग से मिली जानकारी अनुसार वराछा के योगी चौक के निकट स्थित एपल स्क्वेयर अपार्टमेंट की पार्कींग में स्पलेन्डर मोटर साइकिल में लगी एलपीजी गैस की टंकी से गैस निकलने की सूचना मिली थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर की टीम तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गई और लीकेज वाली बाईक को बाहर निकाला।

सांसद पूनम बहन माडम की पुत्री की मौत से दुखी

अहमदाबाद । जामनगर और देवभूमि द्वारका जिले की लोकसभा सीट की भाजपा सांसद सदस्य पूनमबहन माडम की पुत्री की रविवार को सुबह में सिंगापुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई है। विशेष करके परिवार और रिश्तेदारों के साथ जामनगर क्षेत्र के अलावा भाजपा तथा अन्य राज नीतिक पार्टियों में शोक की लहर फैल गई। दीपावली के दौरान दिल्ली में गंभीर रूप से झुलस गई सांसद पूनमबहन माडम की पुत्री शिवानी को दिल्ली, मुंबई और वहां से सिंगापुर उपचार के लिए भर्ती करायी गई थी फिर भी इसे बचाई नहीं जा सकी और उपचार होने के बाद इसकी मौत होने से सांसद माडम तथा जामनगर सहित राज्यभर और उनके परिवार में शोक की लहर फैल गई। दीपावली के दौरान दिल्ली की सांसद पूनमबहन माडम की आवास पर पुत्री के झुलस जाने से उसे लंबे समय तक इलाज के दौरान मुंबई और सिंगापुर उपचार के लिए लायी गई थी। जहां उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई । जामनगर जिले की लोकसभा सीट की भाजपा सांसद सदस्य पूनमबहन माडम की पुत्री की मौत की वजह से सांसद परिवार में शोक की लहर फैल गई।

महिला मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन का उदघाटन अमित शाह करेंगे

गांधीनगर । भाजपा महिला मोर्चा की २१, २२ दिसम्बर को आयोजित होने वाले दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी और व्यवस्था के आयोजन के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और गुजरात के प्रभारी भूपेन्द्र यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जीतु वाघानी के नेतृत्व के तहत श्री कमलम् में रविवार को महत्व की बैठक हुई थी । इस बैठक में राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के लिए बनाये गये २५ जितने विभागों के मुख्य व्यवस्था के इंचार्ज उपस्थित हुए । राष्ट्रीय महामंत्री भूपेन्द्र यादव की उपस्थिति में विभाग वाइज व्यवस्था संदर्भ में रिपोर्टिंग शुरू की गई ।

अडालज के पास स्थित त्रिमंदिर परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की आयोजन बैठक को संबोधित करते हुए भाज पा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेन्द्र यादव ने बताया है कि, गुजरात भाजपा के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता भाग्यशाली है भाजपा के स्थापनाकाल से अभी तक की सबसे बड़ी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अधिवेशन को आयोजन करने का मौका मिला है ।

गुजरात के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अधिवेशन का सुचारू और सफल आयोजन करेंगे ऐसा विश्वास व्यक्त किया है । उन्होंने बताया कि, भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अधिवेशन में भाजपा की संगठन की शक्ति, चुने गये प्रतिनिधियों की शक्ति कम है ऐसे में तमिलनाडु, चेन्नई, आंदामान-निकोबार जैसे राज्य सहित देशभर से अपेक्षित हजारों महिला कार्यकर्ता उपस्थित होगी । गुजरात की भूमि पर 'लघु भारत' इस अधिवेशन में उपस्थित होगी । महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन गुजरात की राजनीति के चाणक्य भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे । राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन के अवसर पर गुजरात के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित होंगे ।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)